

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ रहे ग्लेशियरों की 'ठंडक' अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी

नई दिल्ली। दुनिया भर के ग्लेशियर धीरे-धीरे अपनी ठंडक खोते जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (इस्ता) के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि ग्लेशियर अब तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से खुद को बचाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन यह प्राकृतिक बचाव तंत्र ज्यादा समय तक काम नहीं करेगा।

शोध में पाया गया कि ग्लेशियर अपने आसपास की हवा को ठंडा करके खुद को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखते हैं। यह प्रक्रिया तब होती है जब बर्फ की ठंडी सतह के संपर्क में आने वाली गर्म हवा धीरे-धीरे ठंडी हो जाती है। इसे वैज्ञानिक स्वयं-शीतलन प्रभाव कहते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया स्थायी नहीं है। शोधकर्ताओं का कहना है कि आने वाले दस सालों में यह ठंडक प्रभाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। इसके बाद, जैसे-जैसे जलवायु और गर्म होगी, ग्लेशियरों की सतह का तापमान तेजी से बढ़ेगा और उनका पिघलना और भी तेज होगा। नेचर क्लाइमेट चेंज नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि साल 2022 में स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर डे कॉर्बासिएर पर शोध करते हुए शोधकर्ताओं ने इस बदलाव को नजदीक से महसूस किया है। 2,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस ग्लेशियर पर उन्होंने 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया, जो बर्फ से ढके क्षेत्र के लिए बहुत असामान्य था। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय जैसे विशाल पर्वतीय क्षेत्रों में मौजूद बड़े ग्लेशियर अभी भी अपने आसपास की हवा को ठंडा रख रहे हैं। उनकी सतह से निकलने वाली ठंडी हवाएं नीचे की ओर बहती हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करती हैं। इन हवाओं को काटाबेटिक विंड्स कहा जाता है। लेकिन यह ठंडक स्थायी सुरक्षा नहीं है। यह केवल कुछ दशकों तक ही ग्लेशियरों को संभाले रख सकती है। जैसे-जैसे बर्फ का द्रव्यमान घटेगा, यह ठंडक भी खत्म हो जाएगी और ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे। शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के 62 ग्लेशियरों से आंकड़े एकत्र किए, जिसमें 350 मौसम स्टेशनों के रिकॉर्ड शामिल थे। उन्होंने गर्मियों के दौरान लिए गए हजारों घंटे के तापमान आंकड़ों का विश्लेषण किया।

अध्ययन का निष्कर्ष था कि ग्लेशियरों की सतह का तापमान सामान्य वातावरण की तुलना में धीरे-धीरे बढ़ता है। औसतन जब आसपास का तापमान एक डिग्री बढ़ता है, तो ग्लेशियर की सतह पर केवल 0.83 डिग्री की वृद्धि होती है। यह अंतर ही ग्लेशियरों की 'स्वयं ठंडक' क्षमता को दर्शाता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा, यह अंतर घटता जाएगा। 2030 से 2040 के बीच, यह प्रभाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद घटने लगेगा। इसके बाद ग्लेशियर फिर से गर्म वातावरण से जुड़ जाएंगे और



उनका तेजी से पिघलना शुरू होगा। शोध पत्र में शोधकर्ताओं के हवाले से कहना है कि यह शोध केवल वैज्ञानिक महत्व का नहीं है, बल्कि मानव समाज के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। ग्लेशियर न केवल पृथ्वी की ठंडक बनाए रखते हैं, बल्कि अरबों लोगों के लिए मीठे या ताजे पानी का मुख्य स्रोत भी हैं। अगर उनका पिघलना तेज हो गया, तो आने वाले दशकों में पानी की उपलब्धता पर गहरा असर पड़ेगा, विशेष रूप से एशिया, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों में। लेकिन यह मान लेना कि हम ग्लेशियरों को बचा सकते हैं, अवास्तविक है। वैज्ञानिकों के अनुसार, अब ग्लेशियरों के बड़े पैमाने पर पिघलने को रोका नहीं जा सकता। हमें इस हानि को स्वीकार करते हुए, आगे के नुकसान को सीमित करने पर ध्यान देना होगा। शोध पत्र में शोधकर्ता के द्वारा सुझाव देते हुए कहा गया है कि क्लाउड सीडिंग या ग्लेशियरों को ढकने जैसी तकनीकें केवल अस्थायी समाधान हैं। ये एक गंभीर घाव पर महंगी पट्टी लगाने जैसा है। असली समाधान है कार्बन उत्सर्जन को घटाना और जलवायु परिवर्तन को रोकना है। यह अध्ययन हमें एक स्पष्ट संदेश देता है कि समय बहुत कम है। ग्लेशियरों का पिघलना केवल प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानवजनित संकट है। यदि हम अभी भी अपने कार्बन उत्सर्जन, उद्योगों और उपभोग के तरीकों में परिवर्तन नहीं लाते, तो 21वीं सदी के मध्य तक कई बड़े ग्लेशियर गायब हो जाएंगे।

आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च

ये दो योजनाएं भारत के किसानों का भाग्य बदल देंगी- पीएम मोदी

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि बीते 11 सालों में भारत का कृषि निर्यात करीब-करीब दोगुना हो गया है। अनाज उत्पादन 900 लाख मीट्रिक टन बढ़ गया। फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया है। किसानों के लिए दो नई योजनाओं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये दो योजनाएं भारत के किसानों का भाग्य बदल देंगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं पर सरकार करीब 35 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी।

उन्होंने कहा कि खेती और किसानों हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। यह बेहद जरूरी है कि बदलते समय के साथ खेती और किसान को सरकार का सहयोग मिलता रहे। पीएम मोदी ने कहा कि बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत सुधार किए गए, जिसके परिणामस्वरूप आज दूध उत्पादन में भारत नंबर वन है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। भारत में शहद उत्पादन 2014 की तुलना में दोगुना हो गया है। 25 करोड़ से ज्यादा साइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए हैं। 100 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा है। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपये क्लेम के रूप में किसानों को दिए हैं। बीते 11 सालों में 10 हजार से ज्यादा किसान उत्पाद संघ एफपीओ बने। पीएम मोदी ने कहा कि कार्यक्रम में आने से पहले उनकी अनेक किसानों और मछुआरों से बात हुई। उन्हें कृषि क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के अनुभव सुनने का अवसर मिला। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जो देश के किसानों ने अनुभव की हैं।

सायबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का नया प्लान

अब हर जिले में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पोर्टल पर सक्रिय रहेगी पुलिस टीम



भोपाल । प्रदेश में बढ़ते सायबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अब हर जिले में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पोर्टल पर सक्रिय होगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिसमें नेशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और जेएमआईएस पोर्टल के महत्व को भी बताया गया है, कि इस पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। जानकारी के अनुसार एनसीआरपी पर सभी तरह की सायबर संबंधी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा दी गई है। इस पर थाना और जिला पुलिस कार्यवाही करती है, इस पोर्टल पर महिला एवं बच्चों से संबंधित, वित्तीय धोखाधड़ी सहित अन्य सायबर संबंधी अपराधों की शिकायतें आती हैं। वहीं इस पोर्टल पर सिम ब्लाकिंग, सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध सर्च आदि की भी शिकायत आने लगी है। इन पोर्टल पर आने वाली हर शिकायत पर गंभीरता के साथ जांच किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सिम और आईएमआई नंबर के साथ ही सायबर अपराध की विवरण रिपोर्ट आदि जेएमआईएस पोर्टल पर साझा की जाती है। इस पोर्टल के जरिए राज्य की पुलिस सायबर अपराध जांच से संबंधित गिरफ्तार, जब्ती, पूछताछ रिपोर्ट साझा करे ताकि जिन रिपोर्ट का उपयोग अन्य मामलों के साथ ही अपराधियों की पहचान करने के लिए किया जा सके। वहीं रिपोर्ट किए जाने वाले संदिग्ध बैंक खातों का डाटाबेस भी बैंक अकाउंट बेस्ड इंटरलॉक पर रिपोर्ट किये जाए। जिससे सभी राज्यों को संदिग्ध बैंक

खातों की पहचान और कार्यवाही में मदद मिल सके। सायबर इन्वेस्टिगेशन एसिस्टेंस रिक्रेस्ट (सीआईएआर) सभी जिलों को राज्य के नोडल अधिकारी को एक दूसरे से जोड़ेगा। इसके जरिए दस्तावेज सत्यापन, समन-नोटिस और गिरफ्तारी वारंट भी अपलोड किए जा सकेंगे।

शहर के 33 ब्लैक स्पॉट पर तीन दिनों में युद्ध स्तर पर होगा काम

ईलाज में लापरवाही और अनियमितताएं पाये जाने पर डॉक्टरों की टीम ने क्लीनिक किया सील

इंदौर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार को इंदौर के हर्ष क्लीनिक की जांच की गई। जांच के दौरान कई अनियमितताएं पाये जाने पर हर्ष क्लीनिक सील किया गया है। सीएमएचओ डॉ. माधव हासानी ने जानकारी देते हुए बताया कि गत दिवस एक मरीज की मृत्यु की मीडिया में समाचार प्रकाशन और शिकायत के बाद डॉक्टरों की टीम गठित की गई। कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार हर्ष क्लीनिक की जांच कर पंचनामा बनाया गया। जांच करने पहुंचे डॉक्टरों में स्थानी अहीरवाल, निश्वला गुप्ता, अर्चना मानसिंह, शैतान सिंह, सीमा झंले और जूनी इंदौर थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने डॉ. ज्ञान पंजवानी और डॉ. श्रीचंद बागेचा की उपस्थिति में क्लीनिक खुलवाया। मेडिकल टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान क्लीनिक में 15 बेड का अस्पताल, बड़ी मात्रा में एलोपैथिक मेडिसिन का भंडारण, क्लीनिक में वयस्क व शिशुओं की मेडिसिन बड़ी संख्या में खुली हुई भी देखी गई। साथ ही मेडिसिन में कंपनी व मेन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी से सम्बंधित बिना लेबल के भी मिली। वहीं जिस मरीज की मृत्यु का समाचार समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। उनकी बीमारी से सम्बंधित दस्तावेज भी क्लीनिक में नहीं पाये गए। क्लीनिक में बड़ी मात्रा में मेडिसिन के भंडार पाये जाने पर ड्रा कंट्रोलर अथॉरिटी की पृथक से निरीक्षण व जांच की आवश्यकता भी बताई गई।

कलेक्टर श्री वर्मा ने दुर्घटनाएं रोकने के लिए बुलाई बैठक में तीन विभागों को दिया समय

इंदौर इंदौर शहर में दुर्घटनाएं रोकने के लिए कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने गुरुवार देर शाम को सड़क सुरक्षा के मद्देनजर बैठक आयोजित

की। बैठक में मुख्य रूप से नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी विभाग को तीन दिनों में शहर के चिन्हित 33 ब्लैक

स्पॉट पर कार्य करने की हिदायत दी है।

शहर में ऐसे 33 स्थान चिन्हित किये गए हैं, जहां ब्लैक स्पॉट होने से दुर्घटनाएं हुई हैं। इसलिए प्राथमिक रूप से इन स्थानों पर युद्ध स्तर पर तीन दिनों में साइनेज लगाने के साथ ही लाइट और रम्बल स्ट्रिप अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। तीन दिनों बाद इन सभी स्थानों का वे स्वयं निरीक्षण भी करेंगे। कोई भी दुर्घटना न हो, ऐसे उपाय विभागों द्वारा अनिवार्यता से किये जायें। बैठक में एडीएम श्री रोशन राय सहित नेशनल हाईवे, नगर निगम, एमपीआरडीसी, यातायात पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहें। जिला प्रशासन द्वारा जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं उनमें लवकुश चौराहा, रिजलाय फाटा धार रोड, देवास नाका चौराहा, बेस्ट प्राइज के सामने बायपास रोड, ओमेक्स सिटी बायपास रोड, डेक्थनॉल के सामने

बायपास रोड, टाटा शोरूम के सामने एबी रोड, बिचौली मर्दाना ब्रिज के ऊपर बायपास, तीन इमली चौराहा, रालामण्डल चौराहा बायपास रोड, तेजाजी नगर ब्रिज के ऊपर एबी रोड, कैलोद करताल फाटा बायपास रोड, राऊ गोल चौराहा, आईटी पार्क चौराहा, विशेष जूपीटर हॉस्पिटल के सामने रिंग रोड, प्रभु तौल कांटे के पास नेमावर, ट्रेचिंग ग्राउंड के सामने नेमावर रोड देवगुराडिया, ग्राम माचल, महू डू नीचम रोड घाटाबिछौद, काला सूर फाटा इंदौर धार रोड, ए बी रोड भैरुघाट पुलिया के पास ग्राम कालाकिराय, ए बी रोड अर्जुन बरोदा, डकाच्या ए बी रोड, बुड़ी बरलाई, कल्याण मील, लसुडिया परसार, टीही पुलिया फॉरलेन रोड, पिगडम्बर, माँ वैष्णो ढाबा, इंदौर खंडवा रोड भैरुघाट, इंदौर खंडवा बाई ग्राम और दुधिया पावर हाउस के सामने नेमावर रोड शामिल हैं। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाये।



डॉ सोनल सिंह को मिला बेस्ट टीचर अवॉर्ड

उज्जैन । कायस्थ समाज की बेटी एवं सम्राट विक्रमादित्य विवि की पूर्व प्रोफेसर तथा कला संकाय विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोनल सिंह के नाम से बेस्ट एलआईएस टीचर अवॉर्ड की घोषणा के बाद समाज जनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए डॉ सोनल सिंह का अभिनंदन किया। समाज के लिए यह पल अति गौरवान्वित करने वाले हैं जब समाज की बेटी को इतिहास में पहलीबार इतना बड़ा सम्मान मिला है। उज्जैन कायस्थ समाज अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की कला संकाय की पूर्व संकायाध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आचार्य डॉ. सोनल सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान कायम की है इस अवसर पर समाज अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव सहित उर्मिला श्रीवास्तव, अनुपमा श्रीवास्तव, चेतना श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव, नेहा श्रीवास्तव, शशि श्रीवास्तव, आशीष अग्रना, चेतन श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

डूबने, जहरीला पदार्थ खाने और सड़क दुर्घटनाओं से मचा हड़कंप

भड़वानी. जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों ने लोगों को हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पिछोड़ी में एक व्यक्ति की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान समर सिंह पिता लूनिया निवासी पिछोड़ी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सुपुर्द किया। मामले में मर्ग कायम कर जांच जारी है। इसी बीच मंगलवार रात ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग में सड़क हादसा हो गया। महेश विश्वकर्मा नामक युवक अपनी बाइक पर गेहूं लेकर घर जा रहा था। राजपुर रोड स्थित वेयरहाउस के सामने अचानक वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर भीड़ जमा हो गई और सड़क पर गेहूं बिखर गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार जारी है। वहीं नागलवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवनली निवासी श्रवण ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया और बाद में हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया।

उद्योगपतियों और निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित



भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश, देश का दिल है। नदियों के मायके और बाघों की सहज दृश्यता वाली ये वो पवित्र धरती है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण ने अपना बचपन बिताया और शिक्षा-दीक्षा भी प्राप्त की। मध्यप्रदेश और असम का 5 हजार साल पुराना संबंध है। इतिहास में श्रीकृष्ण और माता रूक्मिणी प्रसंग में मध्यप्रदेश और असम आपस में जुड़े हैं। बावन शक्तिपीठों में से एक देवी कामाख्या शक्तिपीठ असम की धरती पर है और मध्यप्रदेश में कालों के काल बाबा महाकाल विराजमान हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश हृदय प्रदेश होने के साथ आज देश का सबसे उपयुक्त निवेश प्रदेश है। मध्यप्रदेश की देश में केंद्रीय स्थिति, भरपूर बिजली-पानी, कुशल श्रमशक्ति और उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स सुविधाओं से हमारा राज्य उद्योग स्थापना के लिए देश का आइडियल डेस्टिनेशन बन चुका है। मध्यप्रदेश की देश के प्रमुख शहरों से बेहतरीन कनेक्टिविटी भी निवेशकों को अतिरिक्त लाभ देती है। मध्यप्रदेश में निवेश हर मायने में फायदे का सौदा है। उन्होंने असम राज्य के उद्योगपतियों और निवेशकों से आग्रह किया कि वे मध्यप्रदेश में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं और यहां अपने उद्योग एवं निर्माण इकाइयां स्थापित करें। सरकार हर कदम पर निवेशकों को पूरा सहयोग और आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि निवेशक कोई रोजगार आधारित उद्योग लगाते हैं, तो हमारी सरकार बिजली, पानी, कनेक्टिविटी की सुविधा के साथ श्रमिकों के वेतन के लिए 5000 रुपये प्रति श्रमिक की सब्सिडी भी देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को गुवाहाटी के एक निजी होटल में इन्वेस्टमेंट सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश में असम राज्य के उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन कर इस सेशन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों को बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के पहले और सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन मध्यप्रदेश की धरती पर 17 सितम्बर को

किया जा चुका है। यह मेगा टेक्सटाइल पार्क निवेश के लिए एक अनूठा और सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि निवेशक इस टेक्सटाइल पार्क में या मध्यप्रदेश के किसी भी अंचल में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहें, तो हमारी सरकार इसमें सहयोगी और मददगार के रूप में साथ देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने असम राज्य का गौरव स्व. श्री भूपेन हजारिका और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक स्व. श्री जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि असम एक ऐसा राज्य है, जो चाय के पत्ते-पत्ते को सोना बनाकर बेचता है। गुवाहाटी एक बेहद पवित्र नगरी है। नॉर्थ-ईस्ट हमारे लिए भारत को दुनिया से परिचित कराने का गौरवशाली गेट-वे है। मध्यप्रदेश और असम में काफी समानताएं हैं। हम मिलकर कई सेक्टरों में काम कर सकते हैं। हम यहां मध्यप्रदेश में उपलब्ध बहुत सी संभावनाओं की जानकारी लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने के लिए सभी जरूरी साधन-संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश का बाघ और असम का गैंडा दोनों ही जंगल में एक साथ रफ्तार भर सकते हैं। दोनों राज्य मिलकर इन वन्य प्राणियों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश असम को गौर, घड़ियाल और मगरमच्छ दे सकता है। असम हमें गैंडा देकर हमारे वनों को समृद्ध कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीता पुनर्वास प्रोजेक्ट एक ऐसा ही अनुपम उदाहरण है, जिसमें हमने अफ्रीकन चीतों को मध्यप्रदेश की धरती पर बसाया है। इसी तरह हम अन्य विलुप्तप्राय वन्य जीव प्रजातियों को बसाकर उनकी प्रजाति बचा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का बिजली उत्पादन के मामले में देश में एक अलग ही स्थान है। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन मध्यप्रदेश की बिजली से चल रही है। हम ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में तो हम आगे हैं ही, हमारे राज्य में जमीन और पानी पर भी सोलर एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योग-

धंधों और निर्माण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए हम औद्योगिक इकाई स्थापना, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, गुड्स ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध कराने जैसे सभी सेक्टरों में आगे बढ़कर इन्हें प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए सभी राज्यों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक है और तभी हमारा देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा। मध्यप्रदेश और असम दोनों इस लक्ष्य की ओर मिलकर आगे बढ़ेंगे। असम राज्य के फिक्की के अध्यक्ष एवं जीडी धानुका ग्रुप के एमडी डॉ. घनश्याम दास धानुका ने असम के कल्चरल आइकॉन स्व. श्री जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह आयोजन असम और मध्यप्रदेश के लिए देश के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए औद्योगिक विकास का गेट-वे बनेगा। मध्यप्रदेश निवेशकों और उद्योगपतियों को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी नेतृत्व से ही हर क्षेत्र में विकास होता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने इस मामले में लीड ले ली है। असम राज्य के फिक्की के सह-अध्यक्ष एवं बीएमजी इन्फॉर्मेटिक्स प्रालि के निदेशक श्री जयदीप गुप्ता ने कहा कि गुवाहाटी में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव और डेलीगेशन का स्वागत है। यह मां कामाख्या की भूमि है। हम आज असम के सुप्रसिद्ध गायक स्व. जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मध्यप्रदेश देश का दिल है और असम देश के लिए इकॉनॉमिक गेटवे की तरह है। विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए निवेश आधारित यह रोड-शो बेहद अहम साबित होगा तथा इससे दोनों राज्यों के बीच पारदर्शी और प्रगाढ़ रिश्ते कायम होंगे।

श्री सीमेंट प्रा.लि. के श्री मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि हमारी कंपनी सीमेंट उत्पादन में देश में तीसरा स्थान रखती है। मध्यप्रदेश के धार जिले में हमारी कंपनी को यूनिट शुरू करने के लिए जमीन आवंटित हुई है। खनिज विभाग की ओर से हर संभव सहायता मिल रही है। प्रदेश में रोड, रेल नेटवर्क का जाल बिछा है, जो बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करता है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इकोसिस्टम मौजूद है। धार में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन किया है। मध्यप्रदेश का मालवा क्षेत्र कपास उत्पादन का गढ़ है। इससे यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाने वाले निवेशकों के साथ यहां के किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा।

असम स्टेट कॉउंसिल फिक्की के पूर्व अध्यक्ष श्री आशीष फुकोंन ने कहा कि मैंने चाय उद्योग से बिजनेस सेक्टर में कदम रखा था। आशा है कि हमारी अगली डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश होगी। हम पर्यटन क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार मुझसे कहा था कि टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं और जब वे प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार लाल किले से उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में निहित संभावनाओं पर ही जोर दिया था।

शहरों की आबोहवा स्वच्छ बनाने 500 करोड़ से तैयार होंगे नगर वन

तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण, 2030 तक शहरों में बनाएंगे ऑक्सीजन

इंदौर। प्रदेश के बड़े शहरों की हवा घुल रहे प्रदूषण के जहर को कम करने के लिए अब सरकार दो साल पहले बजट में घोषित की गई नगर वन योजना को नए रूप में शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत अगले पांच साल में 500 करोड़ खर्च कर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित अन्य शहरों में बीच में खाली सरकारी जमीन पर नगर वन विकसित किए जाएंगे। यह शहर के फेफड़ों की तरह काम करेंगे और प्रदूषित हवा को सोखकर ताजी ऑक्सीजन देंगे। इससे शहरों के पर्यावरण में सुधार होगा। हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में सामने आया है कि वर्ष 2024-25 में 29 शहरों का एक्वूआइ घटने की बजाय बढ़ गया है। इसके पहले ऐसे शहरों की संख्या 24 थी। इसे देखते हुए नगर वन के लिए तेजी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मुख्यमंत्री नगर वन विकास योजना के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव तय कर लिया है। इसे जल्द कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद इस योजना को लांच किया जाएगा। प्रदेश के नगरों में अभी ढाई करोड़ से अधिक लोग रह रहे हैं और यह आबादी लगातार बढ़ रही है। इसलिए नगरों में ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि नगर वन योजना दो साल पहले बजट में घोषित की गई थी। लेकिन इस पर कुछ ही निकायों में कामहुआ है। अब बिगड़ते पर्यावरण को देखते हुए इस पर नए सिरे से काम शुरू हुआ है। नई योजना के अनुसार 2030 में शहरों की शासकीय और वन भूमि पर नगर वन विकसित होंगे। इन वनों

की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकायों को दी जाएगी। पौधरोपण और रख-रखाव की गुणवत्ता पर ही राशि निर्भर होगी। प्रदेश के नगरों में बढ़ती आबादी के चलते वायु प्रदूषण रोकने के लिए किए जा रहे इंतजाम और उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। क्योंकि वर्ष 2024-25 में पिछले साल की तुलना में 29 जिला मुख्यालयों की हवा की गुणवत्ता सुधरने की बजाय और बिगड़ गई। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्वूआइ) कम होने की बजाय और बढ़ गया है। इनमें देश का सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर भी शामिल है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। जबकि वर्ष 2023-24 में ऐसे नगरों की संख्या 24 थी। एमपीपीसीबी ने इन जिलों को पर्यावरण सुधार के उपाय करने के लिए पत्र भी लिखा था। शहरों में बढ़ती आबादी के कारण पेड़ काटकर हो रहे निर्माण कार्यों, बढ़ते यातायात के साथ ही सड़कों की खराब स्थिति के कारण हवा में लगातार पीएम-10 और पीएम 2.5 की मात्रा बढ़ रही है। इससे अब शहरों का ग्रीन कवर 50 तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए नगरीय निकायों में ग्रीन सेल बनाए जाएंगे। इसमें उन्हीं अधिकारियों-कर्मचारियों को रखा जाएगा जिनकी पौधरोपण और हरियाली बढ़ाने में रुचि है। उन्हें इसका पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कौन से पौधे लगाए जाएं, उनके लिए किस तरह का वातावरण जरूरी है, उनकी देखरेख कैसे करना है। नगर वन विकसित करने के साथ उनकी देखरेख और रखरखाव, विकास आदि का जिमा इस ग्रीन सेल का ही होगा। नगरीय निकायों को इसके लिए 500 करोड़ रुपए तीन किस्तों में दिए जाएंगे। पहले साल 60 प्रतिशत, दूसरे और तीसरे साल 20-20% राशि जारी की जाएगी। पौधों की जीवितता के अनुसार ही यह राशि जारी की जाएगी।

मध्यप्रदेश और असम के बीच वन्य जीव पर्यटन में साझेदारी के लिए होगी विशेष पहल- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने काजीरंगा नेशनल पार्क का किया भ्रमण

चाय बागान में श्रमिकों और बहनों से किया आत्मीय संवाद



भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने असम प्रवास के दौरान रविवार को विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और चाय बागान का भ्रमण किया। उन्होंने बागान में चाय उत्पादन की प्रक्रिया का अवलोकन कर स्थानीय किसानों और श्रमिक बहनों से आत्मीय संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चाय उद्योग

असम का गौरव और अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। परिश्रम, अपनत्व एवं सादगी की धरती असम और मध्यप्रदेश के बीच व्यापार-उद्योग के साथ ईको-टूरिज्म, वन्य जीव पर्यटन की दिशा में भी परस्पर सहयोग, विश्वास और साझेदारी को बढ़ाने के लिए विशेष पहल होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीव संरक्षण की मनमोहक झलक देखी एवं हाथियों को स्नेह से गन्ना खिलाकर दुलार किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां वन्यजीवों के संरक्षण संवर्धन के लिये नवाचारों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उद्यान भ्रमण के दौरान अजगर को प्राकृतिक आवास में छोड़ा। उल्लेखनीय है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे सहित पूर्वी हिमालयी जैव विविधता का केन्द्र है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व-धरोहर घोषित किया गया। यह उद्यान हाथियों, जंगली भैंसों, दलदली हिरणों और विभिन्न पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है। यह उद्यान वन्य जीवों की बड़ी संख्या के साथ वन्य जीव संरक्षण गतिविधियों के लिए भी विख्यात है।